प्रेस विज्ञप्ति

स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया **2021:** कोविड **-19** का एक वर्ष

महामारी ने बहुसंख्य लोगों की आमदनी को घटाया है, जिससे गरीबी में अचानक उछाल आया है

बेंगलुरु, मई 5, 2021:

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट, "स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2021: कोविड -19 के एक वर्ष" आज जारी की जा रही है। यह रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। रिपोर्ट को You Tube Live के माध्यम से दोपहर दो बजे जारी किया जाएगा। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) अमित बसोले द्वारा मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रस्तुति के बाद फरज़ाना अफ़रीदी (प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दिल्ली), यामिनी अय्यर (निदेशक, सेण्टर फॉर पब्लिक पालिसी), उमा महादेवन (प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, , कर्नाटक सरकार), मल्लीगे (कर्नाटक जनशक्ति), और जॉन ड्रेज (अतिथि प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), रांची विश्वविद्यालय) के साथ चर्चा होगी, जिसका संचालन अर्जुन जयदेव (अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)), और रोज़ा अब्राहम (सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट में वरिष्ठ शोधकर्ता) के द्वारा किया जाएगा।

यह रिपोर्ट भारत में कोविड-19 के एक वर्ष का रोज़गार , आमदनी, ग़ैरबराबरी और ग़रीबी पर पड़े प्रभाव का दस्तावेजीकरण करती है। यह नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता की भी जांच करती है जो राहत और सहायता प्रदान करने के लिए किए गए हैं। अंत में, यह निकट और मध्यम अवधि के भविष्य के लिए कुछ नीतिगत सुझाव भी पेश करती है।

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के कुलपति अनुराग बिहार ने कहा कि इस महामारी ने हमारे समाज की वह ढांचागत और नैतिक खामियां उजागर की हैं जो हर बार सबसे कमज़ोर ताब्कों से सबसे अधिक कीमत चुकाने पर मजबूर करती हैं. इसको हमें जड़ से बदलना होगा. यह रिपोर्ट इस दिशा में एक छोटा कदम है. महामारी के एक वर्ष का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट नकट और मध्यम काल के भविष्य के लिए कुछ सबक पेश करती है.

रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया और अधिकांश श्रमिकों की आय को घटाया है, जिनके परिणामस्वरूप गरीबी में अचानक उछाल आया है। महिलाएं और युवा कामगार अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हुए हैं। परिवारों ने कम खाना खाकर, उधार लेकर और परिसंपत्तियों को बेचकर इस संकट से जूझने की कोशिश की है। सरकारी राहत से संकट के सबसे भयानक रूपों से बचाव तो हुआ है, लेकिन सहायता के इन उपायों की पहुंच अधूरी रही है, और कुछ सबसे मजबूर और कमज़ोर श्रमिक और परिवार उनसे वंचित रहे हैं।

रिपोर्ट के मुख्य शोधकर्ता, अमित बसोले, ने कहा कि अतिरिक्त सरकारी सहायता की अभी दो कारणों से तत्काल आवश्यकता है - पहले वर्ष के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और दूसरी लहर के आशंकित प्रभाव से बचने के लिए। इसमें जून महीने से आगे मुफ्त राशन, कॅश ट्रासंफर, मनरेगा का विस्तार और सहरी रोज़गार कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं.

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

1. **रोजगार और आय** की स्तिथि **जून 2020** से सुधरी **लेकिन भरपाई अधूरी ही रही**

क: अप्रैल-मई 2020 के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान तक़रीबन 10 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियाँ चली गईं। इनमें से अधिकांश जून 2020 तक काम पर वापस लौट आये, हालांकि 2020 के अंत तक भी करीब डेढ़ करोड़ श्रमिक बेरोजगार ही रहे। अक्टूबर 2020 में भी परिवारों की प्रति व्यक्ति मासिक आय (₹4,979) जनवरी 2020 की आय (₹5,989) से तक़रीबन हजार रूपये कम रही।

ख: जिन राज्यों में कोविड के मामले औसतन ज़्यादा थे, वहां रोजगार भी ज्यादा गया। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नौकरियों का नुकसान अपेक्षाकृत ज़्यादा हुआ।

ग: जाहिर है कि तालाबंदियों आदि के चलते आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई कमी की वजह से लोगों की आमदनी कम हो गई। हमने पाया है कि गतिशीलता (mobility) में 10% की गिरावट, आय में 7.5% की गिरावट के साथ जुड़ी थी। आनेवाली तालाबंदियों के प्रभाव का आकलन करते समय इस संख्या को ध्यान में रखना उपयोगी होगा।

2. महिलाएं और युवा कामगार अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित थे और कई लोग साल के अंत तक भी काम पर नहीं लौट पाए

क: तालाबंदी के दौरान और उसके बाद के महीनों में, 61% कामकाजी पुरुषों के पास रोजगार रहा और केवल 7% पुरुषों ने अपनी नौकरियाँ गंवाई और काम पर लौट नहीं पाए। इसके मुकाबले, तालाबंदी के दौरान सिर्फ 19% स्त्रियों के पास रोजगार रहा जबकि 47% स्त्रियों ने स्थायी रूप से अपनी नौकरियाँ खो दीं, और 2020 के अंत तक भी वो काम पर लौट नहीं पाई थीं।

ख: युवा श्रमिकों पर महामारी का बहुत असर हुआ था; उनकी नौकरियाँ भी अपेक्षाकृत ज़्यादा गईं और बापस मिली भी कम। दिसम्बर 2020 तक भी 15-24 वर्ष की आयु वर्ग के 33% श्रमिक रोजगार प्राप्त करने में विफल रहे। जबकि इनसे अधिक आयु वाले कामगारों में, यानी 25-44 वर्ष आयु वर्ग में, ऐसे विफल होने वाले सिर्फ 6% थे।

३. अनौपचारिक रोजगार में बड़ी वृद्धि हुई।

तालाबंदी के बाद, कई श्रमिक रोजगार के अधिक अनिश्चित और अनौपचारिक रूपों में वापस आ गए। 2019 के आखिर और 2020 के आखिर के महीनों के बीच औपचारिक क्षेत्र के वेतनभोगी श्रमिकों में से लगभग आधे ने अनौपचारिक काम की तरफ रुख कर लिया – या तो स्व -रोजगार शुरू करदिया (30%), या अनियमित दिहाड़ी करने लगे (10%), या फिर अनौपचारिक क्षेत्र में वेतनभोगी बनकर चले गए (9%)।

4. अधिक गरीब परिवार ज्यादा बुरे तरीके से प्रभावित हुए, नतीजतन गरीबी और गैरबराबरी बढ़ गई है।

क: हालाँकि आय में गिरावट चौतरफा हुई, फिर भी महामारी की मार गरीब घरों पर ज्यादा पड़ी। चित्र 6 से पता चलता है कि अप्रैल और मई के महीनो में सबसे ज़्यादा गरीब 20% परिवारों ने कुछ भी नहीं कमाया। जबकि समृद्ध परिवारों की आमदनी में गिरावट महामारी-पूर्व की तुलना में एक-चौथाई से भी कम हुई। हमारे विश्लेषण के मुताबिक़ आठ कोविड महीनों (मार्च-अक्टूबर) के दौरान सबसे गरीब 10% परिवारों को ₹15,700 का नुकसान हुआ, जो रकम उनकी दो महीने की आय से कुछ ज्यादा ही है।

ख: राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सीमा (₹375 प्रति दिन, बकौल अनूप सतपति कमिटी) से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 23 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर में 15 प्रतिशत अंकों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20 प्रतिशत अंकों का उछाल आया।

5. परिवारों ने भोजन कम करके और कर्ज लेकर इस संकट से जूझा

गुज़ारे के लिए परिवार भोजन कम करने; परिसंपत्तियों को बेचने; और दोस्तों, रिश्तेदारों और देनदारों से अनौपचारिक रूप से (यानी बिना लिखा-पढ़ी के) उधार लेने पर मजबूर हो गए। अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे (CLIPS) में 90% उत्तरदाताओं ने कहा कि लॉकडाउन के कारण भोजन में कमी आयी । इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 20% ने बताया कि लॉकडाउन के छह महीने बाद भी भोजन का सस्तर बेहतर नहीं हुआ था। ये निष्कर्ष अन्य कोविड प्रभाव सर्वेक्षणों के अनुरूप हैं।

6. सरकारी राहत उपायों से मदद तो मिली, लेकिन उनसे वंचित रह जाना भी आम बात थी

राशन और जन धन की पहुँच पर यह रिपोर्ट अलग अलग सर्वेक्षणों से आंकड़े देती है. जन धन के मुकाबले पीडीएस (PDS) की व्यापक पहुंच थी। जहाँ लगभग 90% परिवारों के पास राशन कार्ड था, वहां सिर्फ 50% घरों में एक महिला का अपना जन–धन खाता था।मगर PMGKY की प्रभावकारिता दोनों प्रकार के राहत उपायों के लिए एक जैसी थी। इंडिया वर्किंग सर्वे (कर्नाटक और राजस्थान में एक बड़े पैमाने पर अगस्त–सितंबर 2020 में आयोजित मुख्यतः ग्रामीण यादृच्छिक (random) सर्वेक्षण) से पता चलता है कि 65% कार्ड धारकों (जिनके पास बी पी एल या अंत्योदय राशन कार्ड था) को कुछ PMGKY आवंटन प्राप्त हुआ (यानी सामान्य कोटा से अधिक अनाज) जबकि 35% को केवल अपने सामान्य PDS कोटा मिला (अतिरिक्त अनाज नहीं मिला)। जिन

घरों में स्त्रियों के पास जन–धन खाता था, 60% को एक या उससे अधिक बार पैसा मिला, जबकि 30% को एक बार भी पैसा नहीं मिला (और 10% को इसकी जानकारी नहीं थी)।

7. संकट से मजबूती से उभरने के लिए साहसिक कदम उठाने होंगे

क: कोविड से निबटने के लिए राजकीय वित्तीय योगदान अब तक अनुदार (conservative) रहा है। दूसरी लहर का बढ़ता प्रभाव अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है, और, हमारी पहली लहर के रिपोर्ट के मद्देनज़र, इसका प्रभाव उसके जितना ही, या उससे भी बड़ा, हो सकता है। बल्कि, चूँकि इस दूसरी लहर के वक़्त जब लोगों की बचत ख़त्म हो चुकी है, लोग क़र्ज़ में डूबे हुए हैं और उनके पास पहले से कम विकल्प बचे हैं, दूसरी लहर का रोजगार, आय, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संभवतः पहले से कहीं अधिक घातक असर हो सकता है। राज्य महामारी की रोकथाम एवं जन कल्याण उपायों में सबसे आगे हैं, नतीजतन वे बहुत ही गंभीर वित्तीय समस्या से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए केंद्र सरकार ही यह काम फिलहाल कर सकती है।

ख: हम निम्नलिखित अत्यावश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव देते हैं -

- जून से बाद भी पीडीएस (PDS) के तहत मुफ्त राशन का दिया जाना, कम से कम 2021 के अंत तक।

  ● मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे के तहत (जो जन-धन खातों तक सीमित नहीं होनी चाहिये), यथासंभव अधिक-से-अधिक खस्ताहाल परिवारों को तीन महीने के लिए ₹5,000 का कैश ट्रान्सफर।

  ● मनरेगा (MGNREGA) की पात्रता का 150 दिनों का विस्तार और मजदूरी बढ़ाकर राज्य की न्यूनतम मजदूरी स्तर तक लाना। मनरेगा बजट का विस्तार कम से कम 1.75 लाख करोड़ तक करना।

  ● सर्वाधिक प्रभावित जिलों में पायलट शहरी रोजगार कार्यक्रम – यथासंभव महिला श्रमिकों पर केंद्रित – शुरू करना।

  ● वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रीय योगदान को कम से कम ₹500 तक बढ़ाना।

  ● भवन-एवं-अन्य-निर्माण-श्रमिक (BoCW) अधिनियम के तहत निर्माण कार्य करने वाले सभी मनरेगा श्रमिकों को पंजीकृत श्रमिकों के रूप में स्वचालित नामांकन करना ताकि वे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकें।

  ● आंगनवाड़ी और आशा (ASHA) के 25 लाख कार्यकर्ताओं को छह महीने के लिए ₹ 30,000 (5,000 प्रति माह) का कोविड कठिनाई अलाउंस ।

इन उपायों पर कुल मिलाकर लगभग ₹5.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे कोविड राहत पर कुल राजकोषीय परिव्यय दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5% पर हो जाएगा। हमारा मानना है कि संकट की भयावहता को देखते हुए इतना बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन (fiscal stimulus) बिलकुल उचित है। उदाहरण के लिए, यह कैश ट्रान्सफर सिर्फ पिछले साल में सबसे गरीब 10% परिवारों द्वारा खो दी गई आमदनी के महज़ बराबर का है, दूसरी लहर के प्रभाव की तो बात ही छोड़ दें।

ग: अगर समय रहते हम अभी उपयुक्त उपाय करने में विफल हुए, तो न केवल अल्पकालिक कठिनाईयां बनी रहेंगी, बल्कि महामारी-जनित दीर्घकालिक मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, जिनके चलते वर्षों में अर्जित समाज-कल्याण की उपलब्धियां खोती हुई नज़र आएँगी। बढ़ी हुई गरीबी के साथ-साथ बचत और उत्पादक संसाधनों के नुकसान से गरीबी के जाल (poverty traps) वजूद में आ सकते हैं। घटी हुई घरेलू आमदनी के कारण पोषण और शिक्षा में आई कमियों के दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। स्त्रियों के श्रम बाजार से बड़ी संख्या में बाहर हो जाने से पहले से ही बड़ा लिंग अंतराल (gender gap) लंबे समय के लिए और भी बड़ा हो सकता है। आर्थिक रूप से इन खो दिए गए वर्षों के कारण उत्पादकता एवं कमाई पर हुए दीर्घकालिक परिणामों का प्रभाव युवाओं पर भी पड़ सकता है।

हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट में पेश किया गया विश्लेषण आने वाले महीनो में अत्यावश्यक नीतिगत कार्याय्वाही का आधार बनेगा।

For media queries contact:

Amit Basole – amit.basole@apu.edu.in | +91-96196 49958

Rosa Abraham – rosa.abraham@apu.edu.in | +91-99019 57009

Shivani Naik – shivani.naik@k2communications.in | +91 97498 97597

About Azim Premji University

Azim Premji University was established as a not-for-profit, private university under the Azim Premji University Act 2010. The University has a clear social purpose of working towards a just, equitable, humane and sustainable society. Azim Premji University plays a critical role in developing new talent, building capacity in existing functionaries and creating domain knowledge in the fields of education and in development. The Azim Premji Foundation is the sponsor of the University. The roots of Azim Premji University lie in the learning and experience of a decade of work in elementary education by Azim Premji Foundation. The University is one of the Foundation's key responses to the challenges confronting the education and development sectors in India.